



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 24—मार्च 2, 2018 (फाल्गुन 5, 1939)

No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 24—MARCH 2, 2018 (PHALGUNA 5, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया

(प्रधान कार्यालय, कोलकाता)

कोलकाता, दिनांक 8 जनवरी 2018

सं. 01/2018—बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 की उप-धारा (2) खंड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके तथा केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी से युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, जैसे :-

1. (1) इन विनियमों को युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपलब्ध कराए जाने के अलावा, उन्हें 1 नवंबर 2007 के पहले दिन से प्रभावी होना समझा जाएगा।

2. युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) विनियमन 3 में, -

(i) खंड (एफ) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(एफ) "परिवार" का अर्थ है अधिकारी के पति/पत्नी, पूरी तरह से निर्भरशील अविवाहित बच्चों (सौतेली बच्चों और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों सहित), शारीरिक रूप से चालीस या अधिक प्रतिशत के साथ अक्षम भाई या बहन और सामान्यतः माता-पिता अधिकारी के साथ रहते हैं और पूरी तरह से निर्भरशील हैं।

स्पष्टीकरण:- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एक बच्चे या माता-पिता या शारीरिक रूप से अक्षम भाई या बहन को अधिकारी पर निर्भरशील होना समझा जाएगा, यदि ऐसे बच्चे, माता-पिता, भाई या बहन की मासिक आय प्रति माह 3500 रुपये से अधिक नहीं है।

बशर्ते कि यदि माता-पिता दोनों में से किसी एक की भी आय प्रति माह 3,500 रुपये से अधिक है या माता-पिता दोनों की प्रति माह सकल आय 3500 रुपये से अधिक है, तो माता-पिता दोनों को अधिकारी पर पूरी तरह से निर्भरशील नहीं माना जाएगा।

(ii) खंड (ओ) को छोड़ दिया जाएगा।

3. उक्त विनियम 4 विनियमन,-

(i) उप-विनियमन (4-ए) को छोड़ दिया जाएगा।

(ii) उप-विनियमन (4-ए) को छोड़ दिए जाने के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम को सम्मिलित किया जाएगा, जैसे:-
"1 नवंबर, 2007 से प्रत्येक ग्रेड के सामने उल्लिखित वेतनमान निम्न प्रकार होगा :

(क) शीर्ष कार्यपालक ग्रेड -

स्केल VII = रु. 46800 - 1300/4 - 52000

स्केल VI = रु. 42000 - 1200/4 - 46800

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड

स्केल V = रु. 36200 - 1000/2 - 38200 - 1100/2 - 40400

स्केल IV = रु. 30600 - 900/4 - 34200- 1000/2 - 36200

(ग) मध्य प्रबंधन ग्रेड

स्केल III = रु. 25700 - 800/5 - 29700 - 900/2 - 31500

स्केल II = रु. 19400 - 700/1 - 20100 -800/10 - 28100

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड

स्केल I = रु. 14500-600/7- 18700-700/2- 20100- 800/7-25700.

स्पष्टीकरण - हर अधिकारी, जो 31 अक्टूबर, 2007 को लागू वेतन मान द्वारा परिचालित हैं, उनका वेतन मान चरणबद्ध आधार पर 1 नवंबर, 2007 के इस उप-नियमन के अंतर्गत तय किया जाएगा, अर्थात् संबंधित स्केल में पहले चरण और इसके आगे अनुरूप चरणों में तय किया जाएगा और अगर किसी प्रकार की अन्य व्यवस्था न हो तो सामान्य रूप से वेतन वृद्धि वर्षगांठ की तारीख पर होगी।

(6) उप-नियमों (1), (2), (3), (4) और (5) में कुछ भी नहीं समझा जाएगा जैसा कि इन सभी ग्रेडों में सेवारत अधिकारी, बैंक को हर समय होना चाहिए। "

(4) उक्त विनियम के विनियमन में 5, -

(क) उप विनियमन (1) के लिए, निम्नलिखित उप विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, जैसे :-

"(1) विनियमन 4 के उप-विनियमन (5) के प्रावधान के शर्ताधीन, 1 नवंबर, 2007 को या इसी दिन से, निम्नलिखित के शर्ताधीन, वेतन वृद्धि मंजूर की जाएगी, जैसे:-

(क) विनियमन 4 के उप-विनियमन (5) में निर्धारित वेतनमान में निर्दिष्ट वेतन वृद्धि, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के शर्ताधीन, वार्षिक आधार पर देय होगी और जिस महीने में देय होगा उस महीने के पहले दिन को प्रदान किया जाएगा;

- (ख) जिन कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-I के अधिकारियों ने मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल-II के वेतनमान में पहुंच गए हैं, उच्चतर स्केल के अधिकतम तक पहुंचने के बाद, प्रत्येक तीन पूर्ण वर्षों की सेवा के लिए चार स्टेगनेशन वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे जिनमें से पहले दो, प्रत्येक रु. 800/- का और अगले दो, प्रत्येक रु. 900/- का होगा:

बशर्ते कि द्वितीय स्टेगनेशन वेतन वृद्धि मिलने के बाद 1 नवंबर, 2007 तक जिन अधिकारियों ने तीन साल अथवा अधिक पूरा कर लिया है, उन्हें 1 नवंबर, 2017 को तीसरा स्टेगनेशन वेतन वृद्धि मिलेगी और उक्त अधिकारियों को दूसरा स्टेगनेशन वेतन वृद्धि मिलने के बाद, उनके छह साल पूरे होने के पश्चात 1 नवंबर, 2008 को या उसके बाद एक अतिरिक्त स्टेगनेशन वेतन वृद्धि प्राप्त होगी।

- (ग) जिन मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल-II के अधिकारियों ने मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल-III के वेतनमान में पहुंच गए हैं, उच्चतर स्केल के अधिकतम तक पहुंचने के बाद, प्रत्येक तीन पूर्ण वर्षों की सेवा के लिए तीन स्टेगनेशन वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि पहला स्टेगनेशन वेतन वृद्धि मिलने के बाद 1 नवंबर, 2007 तक जिन अधिकारियों ने तीन साल अथवा अधिक पूरा कर लिया है, उन्हें 1 नवंबर, 2017 से अगली स्टेगनेशन वेतन वृद्धि मिलेगी और उक्त अधिकारियों को पहला स्टेगनेशन वेतन वृद्धि मिलने के बाद, उनके छह साल पूरे होने के पश्चात 1 नवंबर, 2008 को या उसके बाद आगामी स्टेगनेशन वेतन वृद्धि प्राप्त होगी।

पुनः बशर्ते कि जिन अधिकारियों की नियुक्ति अथवा पदोन्नति अगले मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल-III में हुई है, उनके प्रत्येक तीन वर्षों की सेवा पूरी होने के बाद, उन्हें रु. 900/- की हर चार स्टेगनेशन वेतन वृद्धियां मिलेंगी अथवा :

बशर्ते यह भी कि जिन अधिकारियों को 1 नवंबर, 2007 तक दो स्टेगनेशन वेतन वृद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं और दूसरी स्टेगनेशन वेतन वृद्धि मिलने के बाद तीन वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें 1 नवंबर, 2007 को तीसरी स्टेगनेशन वेतन वृद्धि मिलेगी तथा दूसरी स्टेगनेशन वेतन वृद्धि मिलने के बाद छह साल पूरा करने पर 1 नवंबर, 2018 को या उसके बाद उन्हें चौथी स्टेगनेशन वेतन वृद्धि प्राप्त होगी।

स्पष्टीकरण- इस उप-विनियमन के तहत अधिकारियों के अगले उच्चतर स्केल में इस तरह की वेतन वृद्धि की मंजूरी को अधिकारियों की पदोन्नति, साधिकार, अनुलाभ, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के संबंध में हिसाब नहीं किया जाएगा। ये सब उनके मूल पदों के साथ जारी रहेंगे।

(ख) उप विनियमन (2),-

(i) स्पष्टीकरण में, खंड (ई) के बाद और नोट से पहले, निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात्: -

“(एफ) पहला नवंबर, 2017 को और इस दिन से, अन्य सभी समान होने, व्यावसायिक योग्यता वेतन की मात्रा निम्न रूप से संशोधित होगी-

सारणी

जिन्होंने भारतीय बैंकर्स संस्थान से जूनियर एसोसिएट या भारतीय बैंकर्स संस्थान से सर्टिफाइड एसोसिएट परीक्षा पास की है।	स्केल के अधिकतम तक पहुंचने के एक साल बाद, प्रति माह 410/- रुपये।
जिन्होंने भारतीय बैंकर्स संस्थान से सर्टिफाइड एसोसिएट परीक्षा के दोनों भाग पास किया है।	स्केल के अधिकतम तक पहुंचने के एक साल बाद, प्रति माह 410/- रुपये। स्केल के अधिकतम तक पहुंचने के दो सालों बाद, प्रति माह 1030/- रुपये।

बशर्ते एक अधिकारी के अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के बाद, उसने अगर भारतीय बैंकर संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स) का जूनियर एसोसिएट या सर्टिफाइड एसोसिएट (कोई एक या दोनों भाग) की योग्यता प्राप्त की है तो उसे व्यावसायिक योग्यता की पहली किस्त उस योग्यता को प्राप्त करने की तारीख से मंजूर की जाएगी तथा व्यावसायिक योग्यता वेतन की परवर्ती किस्तें व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त जारी होने की तारीख के संदर्भ जारी की जाएंगी :

बशर्ते कि एक ऐसे मामले में जहां किसी अधिकारी ने पहले से ही उपर्युक्त में से कोई भी योग्यता प्राप्त कर ली हो और ऐसी योग्यता प्राप्त करने के कारण कोई वेतन वृद्धि या व्यावसायिक योग्यता वेतन नहीं प्राप्त किया है तो उसे 1 नवंबर 2007 या ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से प्रभावी व्यावसायिक योग्यता वेतन प्रदान किया जा सकता है, ”;

(ii) नोट में, खंड (v) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"(V) अगर 27 अप्रैल 2010 को किसी अधिकारी ने खंड (iv) में निर्दिष्ट योग्यता पहले ही प्राप्त कर ली है और इस तरह की योग्यता प्राप्त करने के कारण कोई वेतन वृद्धि या व्यावसायिक योग्यता वेतन प्राप्त नहीं किया है, तो उसको 1 नवंबर, 2007 अथवा ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से प्रभावी व्यावसायिक योग्यता वेतन मंजूर किया जाएगा।

(सी) उप-विनियमन (3) में, -

(i) खंड (डी) के बाद और नोट से पहले, निम्नलिखित खंड को डाला जाएगा :-

"(ई) 1 नवंबर, 2007 से, अन्य चीजें समान होते हुए, आवास किराया भत्ता के साथ निर्धारित वैयक्तिक वेतन निम्नलिखित दरों पर रहेगा और पूरी सेवा अवधि के लिए स्थिर रहेगा :-

सारणी

वेतन वृद्धि अंश (रु.)	वेतन वृद्धि अंश पर 01.11.2007 को महंगाई भत्ता (रु.)	जहां बैंक का आवास दिया जाता है, वहाँ देय कुल निर्धारित वैयक्तिक वेतन (रुपए)
(क)	(ख)	(ग)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394

(ii) नोट में, खंड (i) और (ii) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे :-

"(I) जैसा कि (बी), (सी), (डी) या (ई) के अंतर्गत सारणी के (सी) कॉलम में इंगित किया गया है, फिक्स्ड पर्सनल भत्ता या फिक्स्ड पर्सनल वेतन, उन अधिकारियों को देय होगा जिनको बैंक-आवास दिया गया है।

(ii) आवास किराया भत्ता के पात्र अधिकारियों के लिए फिक्स्ड पर्सनल भत्ता या फिक्स्ड पर्सनल वेतन, खंड (ई) के अंतर्गत सारणी के कॉलम (ए) एवं (बी) में निर्दिष्ट कुल राशि होगी तथा विनियमन 4 के उप-विनियमों (2), (3), (4) या 5 में यथानिर्दिष्ट संबंधित वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि के समय संबंधित अधिकारी कर्मचारी द्वारा आहरित आवास किराया भत्ता अर्जित किया जाता है।

(iii) नोट के बाद होने वाले खंड (ई) को उसके उप-खंड (v) रूप में पुनःअंकित किया जाएगा तथा इस प्रकार अंकित खंड (v) के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए :-

"(V) एक अधिकारी जिसने उपर्युक्त खंड (ए) के अनुरूप अग्रिम वृद्धि अर्जित की है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुँचने के एक साल बाद एक निश्चित वैयक्तिक भत्ता/निश्चित वैयक्तिक वेतन की मात्रा प्राप्त करेगा जैसाकि खंड (बी), (सी), (डी) या (ई) में ऊपर उल्लिखित है।

5. उपर्युक्त विनियमों के विनियमन में 21, -

(i) उप-विनियमन (3) में, नोट पर ध्यान नहीं दिया जाएगा;

(ii) उप-विनियमन (4) में, नोट पर ध्यान नहीं दिया जाएगा;

(iii) उप-विनियमन (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमन और नोट सम्मिलित किए जाएंगे :-

"(5) 1 नवंबर, 2007 से महंगाई भत्ता वेतन 0.15% पर अखिल भारतीय औसत कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960 = 100 के त्रैमासिक औसत में 2836 से चार अंकों से अधिक की प्रत्येक वृद्धि या गिरावट के लिए देय होगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-विनियमन के प्रयोजनों के लिए, -

(क) महंगाई भत्ते के प्रयोजन के लिए "वेतन" का अर्थ है स्टैगनेशन वृद्धि सहित मूल वेतन;

(ख) जैसाकि विनियमन 5 के उप-विनियमन (2) के स्पष्टीकरण (सी), (डी), (ई) और (एफ) में निर्दिष्ट है, व्यावसायिक योग्यता भत्ता या व्यावसायिक योग्यता वेतन महंगाई भत्ता की श्रेणी का होगा।

6. कथित उप-विनियमों के विनियमन 22 में उप-विनियम (1) और (2) के लिए निम्नलिखित को विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे: -

“(1) 1 नवंबर 2002 से,

- (क) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराया जाता है, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम चरण में मूल वेतन के 1.75% के बराबर राशि अथवा उस आवास का मानक किराया, इन दोनों में जो कम हो, उससे वसूल किया जाएगा।
- (ख) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है, वह निम्नलिखित सारणी में निर्दिष्ट दरों पर, आवास किराया भत्ता के लिए पात्र होगा:-

सारणी

जहां कार्यक्षेत्र निम्नवत है	भुगतान योग्य आवास किराया भत्ता
(1)	(2)
(i) प्रमुख “ए” क्लास शहर एवं समूह ‘ए’ में प्रोजेक्ट एरिया सेंटर,	वेतन का 8.5%
एरिया I में अन्य स्थान और समूह बी में प्रोजेक्ट एरिया सेंटर,	वेतन का 7.5%
अन्य स्थान	वेतन का 6.5%:

बशर्ते, यदि कोई अधिकारी किराया रसीद प्रस्तुत करता है तो उसकी आवास सुविधा के लिए, उसने जो वास्तविक किराया भुगतान किया है, उसके निर्धारित वेतनमान के पहले चरण के 1.75% से अधिक आवास किराया भत्ता उसे दिया जाएगा जो कि उपर्युक्त सारणी के कॉलम (2) के अनुसार देय आवास किराया भत्ता का अधिकतम का अधिकतम 150% होगा।

(2) 1 नवंबर, 2007 से -

- (क) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवास प्रदान किया जाता है, तो उसके निर्धारित वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 1.20 प्रतिशत के बराबर राशि अथवा आवास के लिए मानक किराया में से जो कम हो, उससे वसूल किया जाएगा;
- (ख) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवास प्रदान नहीं किया जाता है, तो वह निम्न सारणी में निर्दिष्ट दरों पर, आवास किराया भत्ता पाने का पात्र होगा :-

सारणी

जहां कार्यक्षेत्र निम्नवत है	भुगतान योग्य आवास किराया भत्ता
(1)	(2)
प्रमुख “ए” क्लास शहर और समूह ‘ए’ में प्रोजेक्ट एरिया सेंटर,	वेतन का 8.5%
एरिया I में अन्य स्थान और समूह बी में प्रोजेक्ट एरिया सेंटर	वेतन का 7.5%
अन्य स्थान	वेतन का 6.5%

बशर्ते, यदि कोई अधिकारी किराया रसीद प्रस्तुत करता है तो उसकी आवास सुविधा के लिए, उसने जो वास्तविक किराया भुगतान किया है, उसके निर्धारित वेतनमान के पहले चरण के 1.20% से अधिक आवास किराया भत्ता उसे दिया जाएगा जो कि उपर्युक्त सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित उपर्युक्त दरों के अनुसार देय आवास किराया भत्ता का अधिकतम 150% होगा।

नोट- अपने मालिकाना आवास की कीमत से जुड़े आवास किराया भत्ते के लिए अधिकारियों के दावे आवास किराया भत्ते के 150 प्रतिशत तक सीमित होगा। ”;

7. कथित विनियमों के विनियमन 23 में, -

- (i) उप-विनियमन (1) में, “01 नवम्बर 2002” आंकड़ों, अक्षरों और शब्दों के लिए “01 नवंबर 2007” आंकड़े, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे -
- (ii) उप-विनियमन (2) में, “01 नवंबर 2002, आंकड़ों, अक्षरों और शब्दों के लिए “01 नवंबर 2007” आंकड़े, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) उप-विनियमन (3), (4) और (5) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किए जाएंगे :-

"(3) 01 नवंबर, 2007 से कोई अधिकारी ऐसे क्षेत्र में सेवा कर रहा है, जिसे ग्रुप 'ए' या ग्रुप 'बी' में प्रोजेक्ट एरिया के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, तो वह ग्रुप 'ए' या ग्रुप 'बी' एरिया के वर्गीकरण के अनुसार रु. 290/- प्रति माह अथवा रु. 255/- प्रति माह की दर से प्रोजेक्ट एरिया क्षतिपूर्ति भत्ता पाने का पात्र होगा।

(4) 1 नवंबर, 2007 को और इस दिन से, यदि कोई अधिकारी शैक्षणिक वर्ष के बीच में, एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित हो जाता है और यदि पूर्व स्थान पर उसके एक या एक से अधिक बच्चे स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो सभी बच्चों के संबंध में वे 700/- रुपये प्रति माह मध्य-शैक्षणिक वर्ष में स्थानांतरण भत्ता के लिए पात्र होंगे, जहां वह रिपोर्ट करता है, बशर्ते कि पूर्व स्थान पर सभी बच्चों ने पढ़ाई बंद की हो तो ऐसा भत्ता समाप्त हो जाएगा।

(5) 1 मई 2010 से, यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया हो, तो वह उस पद से जुड़ी परिलब्धि प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, जिसके लिए उसे प्रतिनियुक्त किया गया है, या वह अपने वेतन के 7.75 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता आहरण करता है, अधिकतम 2300/- रुपये प्रति माह और ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है, जो उसे उसी स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने की स्थिति में मिलते।

बशर्ते कि यदि उसकी प्रतिनियुक्ति से पूर्व, उसकी तैनाती के स्थान पर ही स्थित किसी संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे अपने वेतन के 4 प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता, अधिकतम 1200/- रुपये प्रति माह प्राप्त होगा:

बशर्ते यह भी कि किसी अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे उसके वेतन का 4%, अधिकतम 1200/- प्रति माह प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा ";

(iv) उप-विनियमन (8) के लिए, निम्न उप-विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(8) 1 नवंबर 2007 को और इस दिन से, यदि एक दिन के दौरान कार्य-घंटे को दो घंटों के न्यूनतम अंतराल के साथ विभाजित किया जाता है, तो एक अधिकारी 165/- रुपये प्रति माह की दर से स्प्लिट ड्यूटी भत्ता के लिए योग्य होगा।";

(v) उप-विनियमन (10) में, -

(क) "नवंबर 2002 का पहला दिन" के अंकों, अक्षरों और शब्दों के लिए, "नवंबर, 2007 का पहला दिन" अंकों, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) सारणी के लिए, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

सारणी

स्थान (1)	दर (2)
(i) 1000 मीटर की ऊंचाई और इससे अधिक, लेकिन 1500 मीटर से कम एवं मर्करा टाउन	2% वेतन के साथ अधिकतम 550/- रुपये प्रति महीने
(ii) 1500 मीटर की ऊंचाई और इससे अधिक, लेकिन 3000 मीटर से कम	2½% वेतन के साथ अधिकतम 680/- रुपये प्रति महीने
(iii) 3000 मीटर की ऊंचाई और इससे अधिक	5% वेतन के साथ अधिकतम 1570/- रुपये प्रति महीने ";

8. उक्त विनियम के विनियमन 24 में, उप-विनियमन (1) में, खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(क) चिकित्सा व्यय- 1 नवंबर, 2007 से, एक अधिकारी स्वयं और परिवार के चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, जो अधिकारी द्वारा उक्त व्यय संबंधी अपने प्रमाण पत्र के विवरण के आधार पर नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट राशि के अनुसार दावा करने पर दिया जायेगा, अर्थात्: -

सारणी

ग्रेड	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन ग्रेड	रु. 5100 या खर्च की गई राशि, जो भी कम हो.
वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष कार्यपालक ग्रेड	रु. 6320 या खर्च की गई राशि, जो भी कम हो.

नोट- (i) एक अधिकारी को देय चिकित्सा सहायता राशि, अगर उसने नहीं लिया है, तो उसे जमा करके एक बार उसका तीन गुना राशि एक साथ लेने के लिए अनुमति दी जा सकती है;

(ii) वर्ष के लिए 2007, चिकित्सा सहायता योजना के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दो महीने अर्थात् नवंबर और 2007 के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ा दी जाएगी। 2007 दिसंबर

स्पष्टीकरण इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए -

(i) अधिकारी के मामले में अस्पताल में भर्ती संबंधी शुल्क का 100 प्रतिशत और उनके परिवार के सदस्यों के मामले में 75% की प्रतिपूर्ति की जाएगी, उन सभी मामलों में जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है या;

(ii) 1 मई, 2010 को और इस दिन से इस विनियमन के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती संबंधी खर्च की प्रतिपूर्ति, कामगार कर्मचारियों के लिए द्विपक्षीय समझौता दिनांक 27 अप्रैल, 2010 के तहत निर्धारित अस्पताल में भर्ती योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार सशर्त नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन होगी, अर्थात् -

सारणी

(क) कनिष्ठ प्रबंधन स्केल I और मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल II और III.	(i) बिस्तर प्रभार स्वयं - रु. 700 प्रति दिन परिवार - रु. 525 प्रति दिन (ii) अन्य प्रभार कामगार कर्मचारियों के लिए लागू अस्पताल में भर्ती योजना के तहत निर्धारित सीमाओं के 125% के स्केल पर।
(ख) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल IV और V और शीर्ष कार्यपालक ग्रेड स्केल VI एवं VII	(i) बिस्तर प्रभार स्वयं - रु. 900 प्रति दिन परिवार - रु. 625 प्रति दिन (ii) अन्य प्रभार कामगार कर्मचारियों के लिए लागू अस्पताल में भर्ती योजना के तहत निर्धारित सीमाओं के 150% के स्केल पर।

9. उक्त विनियम के विनियमन 25 में, उप-विनियमन (2) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(2) उप-विनियमन (1) में निहित के बावजूद, अधिकारी द्वारा भुगतान करने पर, अधिकारी को आवासीय मकान बैंक द्वारा 1 नवंबर 2007 से उस वेतन के पहले चरण के मूल वेतन के 1.20 प्रतिशत राशि के बराबर, जिसमें वह कार्यरत है या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, पर उपलब्ध करवाया जा सकता है।

बशर्ते कि जहां अधिकारी को इस तरह के निवास में फर्नीचर सहित आवास प्रदान किया जाता है, उसके वेतन के पहले चरण के मूल वेतन के 0.25 प्रतिशत राशि के बराबर अतिरिक्त, जिसमें वह कार्यरत है, बैंक द्वारा उनसे वसूल किया जाएगा:

बशर्ते और कि जहां ऐसे आवासीय मकान बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, इसकी बिजली, पानी, गैस और संरक्षण से संबंधी प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा।"

10. उक्त विनियम के विनियमन 36 में, उप-विनियमन (2) के बाद में, निम्नलिखित उप-विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(3) मई 2010 के पहले दिन से, अधिकतम 12 महीने की अवधि के भीतर, हिस्टेरेक्टोमी के मामले में अधिकतम 45 दिन तक की छुट्टी भी दी जा सकती है।"

11. उक्त विनियम के विनियमन 41 में, उप-विनियमन (4) में, खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

'(क) विराम भत्ता - 1 मई, 2010 को और इस दिन से, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में निर्धारित ग्रेड या स्केल के अधिकारी 'प्रति दिन' विराम भत्ता अनुरूपी दर से प्राप्त करने का हकदार होगा, जो स्तंभ (2) में दिया गया है, अर्थात्: -

सारणी

अधिकारियों का ग्रेड/स्केल	प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहर	क्षेत्र- I	अन्य स्थान
(1)	(2)		
	रु.	रु.	रु.
स्केल IV के अधिकारियों और इससे उपर	1000	800	700
अधिकारी, स्केल I/II/III	800	700	600

बशर्त कि स्केल IV और इसके उपर के अधिकारियों के मामले में, चार महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्टेशन से बाहर कार्य करते समय दिए जाने वाले विराम भत्ता 1200/- रुपये होगा और स्केल I या II या III के अधिकारियों के लिए प्रति दिन विराम भत्ता और रु. 1000/- होगा:

बशर्त कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम है लेकिन चार घंटे से अधिक है, तो उपर्युक्त दरों में विराम भत्ता की आधी दर देय होगी।

स्पष्टीकरण - "प्रति दिन" विराम भत्ता की गणना करने का अर्थ है चौबीस घंटे या उसके बाद के किसी भी भाग के लिए, हवाई यात्रा के मामले में रिपोर्टिंग समय और अन्य मामले में प्रस्थान के समय को माना जाएगा और जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है, वहां "प्रति दिन" का अर्थ है आठ घंटे से कम की अवधि नहीं होनी चाहिए। '

12. उक्त विनियमनों के विनियम 42, उप-नियमन (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमन शामिल किया जाएगा, अर्थात्: -

"(4) 1 मई 2010 को और उसके बाद से, स्थानांतरित होने वाला अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा, आदि से संबंधित व्यय के लिए एक मुश्त राशि आहरित करने का पात्र होगा, जैसा कि नीचे दी गई सारणी में निम्न रूप से उल्लिखित है, -

सारणी

ग्रेड	एकमुश्त
शीर्ष कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन	रु.12,000
मध्य प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन	रु.9,000.

13. उक्त विनियमनों के विनियम 44, उप-नियमन (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमन को शामिल किया जाएगा अर्थात्: -

"बशर्त कि कनिष्ठ प्रबंधन वेतनमान के किसी अधिकारी 1 मई 2010 से लागू, रियायती छुट्टी यात्रा करते समय, सबसे कम किराए वाले इकनॉमी श्रेणी में हवाई यात्रा करने का हकदार होगा, इस मामले में प्रतिपूर्ति वास्तविक किराए की होगी या किराया दूरस्थ यात्रा के लिए ट्रेन द्वारा एसी प्रथम श्रेणी के किराया, जो भी कम हो, के समान होगी, जहां की दूरी 1000 किलोमीटर से कम है, मध्य प्रबंधन वेतनमान II और मध्य प्रबंधन वेतनमान III के लिए रियायती छुट्टी यात्रा के संबंध में एक समान नियम लागू होगा।"

14. उक्त विनियमनों के विनियम 45 में, -

(I) उप-विनियमन में (1) निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"बशर्त कि 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा के लिए नियुक्त अधिकारियों के लिए कोई भविष्य निधि नहीं होगी।";

(ii) उप-विनियमन (3) में, खंड (बी) के बाद और नोट से पहले, निम्नलिखित खंड शामिल है, अर्थात्: -

"(ग) जो अधिकारी अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत शामिल हैं, वे पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुन सकते, वे अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत रहेंगे।";

(iii) उप-विनियमन के बाद, (3) निम्न उप-नियमन शामिल है, अर्थात्:

"(4) 1 अप्रैल 2010 को दिन या उसके बाद बैंक की सेवा में नियुक्त होने वाले अधिकारियों को एक निश्चित अंशदायी पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा, जहां अधिकारी अपने वेतन का 10 प्रतिशत + महंगाई भत्ता का अंशदान करेगा और बैंक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित भारत सरकार की अधिसूचना एफ सं.5/7/2003-ईसीबी एंड पीआर दिनांक 22 दिसंबर, 2003, समय-समय पर संशोधित। "अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान नई पेंशन योजना के अनुसार समान राशि का ही अंशदान किया जाएगा।

15. उक्त नियमों की अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के लिए अनुसूची (विनियमन के उप-विनियमन (2) देखें)

1 नवंबर, 2007 से, एक अधिकारी विशेष क्षेत्र भत्ता के लिए तब तक पात्र होगा जब तक कि उसे पूरी तरह या आंशिक रूप से हटाया नहीं जाता है या संशोधित नहीं किया जाता है, जैसा कि नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित है:-

क्रम सं.	क्षेत्र	भत्ता (रु.)	
		रु.14,700/- से कम वेतन	रु.14,700/- से अधिक वेतन
1	2	3	4
1.	मिजोरम		
	(क) मिजोरम का चिंपटुपुई जिला एवं मिजोरम जिले के लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर दूर का क्षेत्र	2000	2600
	(ख) मिजोरम के लुंगलेई शहर से छोड़कर पूरा किलोमीटर बाद के क्षेत्र को 25 लुंगलेई जिला	1600	2100
	(ग) मिजोरम के पूरे आइजवाल जिला	1200	1500
2.	नागालैंड	1600	2100
3.	अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह		
	(क) उत्तर अंदमान, मध्य अंदमान, छोटा अंदमान, निकोबार एवं नारकोडम द्वीप समूह	2000	2600
	(ख) दक्षिण अंदमान (पोर्ट ब्लेयर समेत)	1600	2100
4.	सिक्किम	2000	2600
5.	लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह	2000	2600
6.	असम	320	400
7.	मेघालय	320	400
8.	त्रिपुरा		
	(क) त्रिपुरा का दुरुह क्षेत्र	1600	2100
	(ख) पूरे त्रिपुरा में दुरुह क्षेत्र को छोड़कर	1200	1500
9.	मणिपुर	1200	1500
10.	(क) अरुणांचल प्रदेश		
	(ख) अरुणांचल प्रदेश का दुरुह क्षेत्र	2000	2600
	(क) पूरे अरुणांचल प्रदेश में दुरुह क्षेत्र को छोड़कर	1600	2100
11.	जम्मू एवं कश्मीर		
	(क) कछुआ जिला:	2000	2600
	नियाबत बानी, लोही, मल्हार एवं मछोडी		
	(ख) उधमपुर जिला:		
	(i) डुडु बसंतगढ़, लांदर भामग इलाका, भाग 2(बी) जो अंतर्निहित हैं उनके	2000	2600
	(ii) अलावा		

	(iii) कंबन की ओर से गोएल तक का क्षेत्र एवं तहसील मोड़ में कसाई की ओर से अर्नास तक का.	1600	2100
	(ग) डोडा जिला: किश्तवाड़ तहसील में पैड़र एवं निबात का	2000	2600
	(घ) लेह जिला : जिसे के सभी सभी स्थान	2000	2600
	(ङ) बारामुला जिला (i) पूरा गुरेज-निराबात, तंगदार उप-मंडल एवं कर्नाल इलाका	2000	2600
	(ii) मत्तिल	1600	2100
	(च) पुंछ एवं राजौरी जिला : पुंछ एवं राजौरी जिले के क्षेत्र पुंछ शहर एवं राजौरी और सुंदरबानी तथा इन दो जिलों के अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर।	1200	1500
	(छ) मद में शामिल नहीं होने वाले क्षेत्र उपर्युक्त (क) से (च) तक, लेकिन जिनकी दूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 किलोमीटर के भीतर है या वे स्थान जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अपने कर्मचारियों के लिए सीमा भत्ता पाने के लिए हकदार घोषित किए गए हैं।	1200	1500
12.	हिमाचल प्रदेश (क) चंबा जिला (i) पंजी तहसील, भारमौर तहसील, पंचायत : बडगौन, बजोल, देओल कुगती, नयागाम एवं टुंडा, गाँव: ग्राम पंचायत जगत का घाटू, ग्राम पंचायत चौथा का कंसारी	2000	2600
	(ii) उपरोक्त मद (i) में शामिल पंचायत और गांवों को छोड़कर भर्मूर तहसील।	1600	2100
	(iii) भातियात तहसील, चुराह तहसील, डलहौसी टाउन में झांदु (बानीखेत सहित) पंचायत।	1200	1500
	(ख) किन्नौर जिला: (i) उपर्युक्त में निर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर, असरंग, चितकुल और हांगो कुनो/चरंग पंचायत, छोटा खंबा, नाथपा और रूपी ग्राम पंचायतों को मिला कर 15/20 क्षेत्र, पूह उप-खंड।	2000	2600
	(ii) उपर्युक्त (क) में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर समग्र जिला	1600	2100
	(ग) कुल्लु जिला: (i) निर्माद तहसील का 15/20 क्षेत्र, जिसमें खरग, कुशवर और सरगा के ग्राम पंचायत शामिल हैं	2000	2600
	(ii) बाहरी- सारज (जाकट-खाना और निर्माद तहसील में बुरो के गांवों को छोड़कर) और बाहरी सिराज क्षेत्र को छोड़ कर पूरा जिला और पांड्राबिस के परगना लेकिन निर्माद तहसील के जगत-खाना और बुरो गांवों सहित	1200	1500
	(घ) लाहौल एवं स्पीति जिला: लाहौल एवं स्पीति का समग्र क्षेत्र	2000	2600
	(ङ) शिमला जिला : (च) रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें कुट, लाबाना-सदाना, सरपारा और चाडी-ब्रांडा के पंचायत शामिल हैं।	2000	2600
	(i) डोरा-कावर तहसील, रामपुर में गोरखली ग्राम पंचायत, कासापथ तहसील और मुनीश, परगाना सरहान के घोरी चाइबिस।	1600	2100
	(ii) चोपाल तहसील और घोरिस, पंजगांव, पट्सनौ, नौबिस और परगाना सरहान के तीन कोटि, तकलेश क्षेत्र का देवती ग्राम पंचायत, परगाना बरबिस, कस्बा रामपुर और रामपुर तहसील के रामपुर परगाना के घोरी नोग, शिमला टाउन और इसके उपनगरों (धल्ली, जाटोग, कासुंप्ती, माशोब्रा, तारादेवी और तुतु)।	1200	1500

	(छ) कांगड़ा जिला: i) बड़ा भांगल और छोटा भांगल के क्षेत्र	1600	2100
	(ii) कांगड़ा जिले के धर्मशाला टाउन और नगरपालिका की सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय, लेकिन धर्मशाला टाउन में शामिल-महिला आईटीआई, दरी, मैकेनिकल वर्कशॉप, रामनगर, बाल कल्याण और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिस, शाकोह, लोयर शाकोह में सीआरएसएफ कार्यालय, कांगड़ा मिल्क सप्लाई स्कीम, दुगियर, एचआरटीसी कार्यशाला, सदर, ज़ोनल मलेरिया कार्यालय, दारी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्टरी, दरी, आईपीएच उप-प्रभाग, दान, निपटान कार्यालय, शामनगर, हिना परियोजना, शामनगर कांगड़ा जिले के पालमपुर टाउन, पालमपुर में एचपीकेवीवी कैपस और इसके नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय, लेकिन इसमें पालमपुर टाउन शामिल है- एच.पी. कृषि विश्वविद्यालय कैम्पस, मवेशी विकास कार्यालय/जर्सी फार्म, बानुड़ी, रेशम कृषि कार्यालय/इंडो-जर्मन कृषि कार्यशाला/एचपीपीडीब्ल्यूडी डिवीजन, बंडला, इलेक्ट्रिकल उप-प्रभाग, लोहाना, डी.पी.ओ. निगम, बंडला, इलेक्ट्रिकल एच ई एस ई डी डिवीजन, घुग्गर	1200	1500
	(ज) मंडी जिला: जोगिंदरनगर तहसील की छुहर घाटी, थानाग तहसील में बगरा, चट्टी, छोटधर, गरागुसैन, गतू, गरयास, जंजहली, जयार, जोहर, कलहानी, कालवन, खोलानाल, लोथ, सिलीबागी, सोमाचान, थछधर, ताची, थाना, धरमपुर ब्लॉक के पंचायत - बिंग, कमला, सकलाना, तन्यार और ताराखोलह, कारसोग तहसील के पंचायत- बालिधर, बागरा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुदी, मांज, पेखी, सैंजू, सराहन और तेबन, सुंदरनगर तहसील के पंचायत - बोही, बातवाड़ा, धन्यारा , पौरा-कोठी, सेरी और शोजा	1200	1500
	(झ) सिरमौर जिला: बानी के पंचायत, बखाली (पछाड तहसील), भरोग भेनेरी (पाओंता तहसील), बिड़ला (नहान तहसील), डिब्बर और (नहान तहसील) और थाना कासोगा (पछाड तहसील) थांसगिरि ट्रैक्ट	1200	1500
	(ञ) सोलन जिला : मंगल पंचायत.	1200	1500
	(ट) उपर्युक्त मद (क) से (ञ) तक शामिल नहीं किए गए हिमाचल प्रदेश के अवशिष्ट क्षेत्र	320	400
13.	उत्तर खंड चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिले के अंतर्गत क्षेत्र	2000	2600

विवरणात्मक ज़ापन

ऐसे विनियम जिन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव दिए गए हैं, वे सब संबंधित बैंकों द्वारा इस संबंध में दिए गए विशेष अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की तरफ से भारतीय बैंक संघ और शीर्ष स्तर के बैंकों के अधिकारियों के संघों के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त टिप्पण के सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार हैं। इसलिए, इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा

ह./- अपठनीय

(महाप्रबंधक (मा.सं.))

कृते युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया प्र. का.

टिप्पण : भारत के राजपत्र में दिनांक _____ को मुख्य विनियम प्रकाशित हुआ था और इसके बाद निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया, जैसे :-

1. सं. 01/2018, दिनांक 08/01/2018
- 2.

UNITED BANK OF INDIA
(HEAD OFFICE : KOLKATA)

Kolkata, the 8th January 2018

No.01/2018—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the United Bank of India, the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the United Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979, namely:-

1. (1) These regulations may be called the United Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2017.
(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of November, 2007, except as otherwise provided in these regulations.
2. In the United Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,-
 - (i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-
 '(f) "family" means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), physically challenged brother or sister with forty per cent, or more disability and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer'.
 Explanation.- For the purposes of this clause a child or parent or physically challenged brother or sister shall be deemed to be dependent on the officer if the monthly income of such child, parent, brother or sister does not exceed Rs. 3,500 per month.
 Provided that if the income of one of the parents exceeds Rs. 3,500 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs. 3,500 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.'
 - (ii) Clause (o) shall be omitted.
3. In regulation 4 of the said regulations,-
 - (i) sub-regulation (4A) shall be omitted;
 - (ii) after sub-regulation (4A) as so omitted, the following sub-regulations shall be inserted, namely:-
 "(5) With effect from the 1st November, 2007, the scales of pay specified against each grade shall be as under :
 - (a) Top Executive Grade
 Scale VII = Rs. 46800 – 1300/4 – 52000
 Scale VI = Rs. 42000 - 1200/4 – 46800
 - (b) Senior Management Grade
 Scale V = Rs. 36200 – 1000/2 – 38200 – 1100/2 - 40400
 Scale IV = Rs. 30600 – 900/4 – 34200– 1000/2 – 36200
 - (c) Middle Management Grade
 Scale III = Rs. 25700 - 800/5— 29700 - 900/2 - 31500
 Scale II = Rs. 19400 - 700/1 - 20100 -800/10 - 28100
 - (d) Junior Management Grade
 Scale I = Rs. 14500-600/7- 18700-700/2- 20100- 800/7-25700.

Explanation.- Every officer who is governed by the scales of pay in force as on the 31st October, 2007 shall be fitted in the scale of pay set out in this sub-regulation as on 1st November, 2007 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.
- (6) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades."
4. In regulation 5 of the said regulations, -
 - (a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation, shall be substituted, namely: -
 "(1) Subject to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 4, on and from the 1st November, 2007, the increments shall be granted subject to the following, namely: -

- (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (5) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II after reaching maximum of the higher scale shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which first two shall be Rs. 800 each and next two Rs. 900 each:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the second stagnation increment as on 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on 1st November, 2007 and another stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of second stagnation increment;

- (c) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs. 900 each for every three completed years of service:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the first stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the next stagnation increment with effect from the 1st November, 2007 and a subsequent stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of the first stagnation increment:

Provided further the officers appointed to or promoted in substantive Middle Management Grade Scale III, shall be eligible for four stagnation increments of Rs. 900 each for every three completed years of service or :

Provided also that the officers who have already received two stagnation increments and completed more than three years of service after receipt of second stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on the 1st November, 2007 and the fourth stagnation increment, on or after the 1st November, 2008 on completion of six years after receipt of second stagnation increment.

Explanation.- Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.

- (b) in sub-regulation (2),-

- (i) in the Explanation, after clause (e) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(f) on and from the 1st day of November, 2007, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as under:-

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs. 410 per month one year after reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs. 410 per month after one year on reaching maximum of the Scale. (ii) Rs. 1030 per month after two years on reaching maximum of the Scale;

Provided that an Officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay:

Provided further that in a case where an officer, has already acquired any of the above qualifications and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he may be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st November 2007 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later.”;

- (ii) in the Note, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

“(v) if an officer, as on the 27th April 2010 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification,

he shall be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st day of November, 2007 or the date of acquiring such qualification, whichever is later.”;

(c) in sub-regulation (3),-

(i) after clause (d) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(e) on and from the 1st November, 2007, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:-

TABLE

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on 01.11.2007 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(A)	(B)	(C)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394”,

(ii) in the Note, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (C) of the Table under clauses (b), (c), (d) or (e) shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (A) and (B) of the Table under clause (e) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4) or (5) of regulation 4 is earned.”;

(iii) clause (e) occurring after the Note shall be renumbered as sub-clause (v) thereof and for clause (v) as so numbered, the following clause be substituted, namely:-

“(v) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d) or (e) above, one year after reaching the maximum of the scale”;

5. In regulation 21 of the said regulations, -

(i) in sub-regulation (3), the Note shall be omitted;

(ii) in sub-regulation (4), the Note shall be omitted;

(iii) after sub-regulation (4), the following sub-regulation and Note shall be inserted, namely:-

“(5) On and from the 1st day of November, 2007, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.15% of Pay.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation,-

(a) “pay” for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments;

(b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d), (e) and (f) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance’.

6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulations (1) and (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

“(1) On and from the 1st day of November, 2002,

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
Other places	6.5% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.75 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

- (2) on and from the 1st day of November, 2007, -

- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.20 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely: -

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.20 per cent of Pay in the first stage of the Scale of Pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) above.

Note.- The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of House Rent Allowance as hitherto.”;

7. In regulation 23 of the said regulations,-

- (i) in sub-regulation (1), for the figures, letters and words “1st day of November 2002”, the figures, letters and words “1st day of November 2007” shall be substituted;
- (ii) in sub-regulation (2), for the figures, letters and words “1st day of November 2002, the figures, letters and words “1st day of November 2007” shall be substituted;
- (iii) for sub-regulations (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-
- “(3) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs. 290 per month or Rs. 255 per month according to the classification of area as Group A or Group B.
- (4) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs. 700 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.
- (5) On and from the 1st day of May, 2010, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum Rs. 2300 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank’s service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs. 1200 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs. 1200 per month.”;

- (iv) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(8) on and from the 1st day of November 2007, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs. 165 per month.”;

- (v) in sub-regulation (10),-

- (a) for the figures, letters and words “1st day of November 2002”, the figures, letters and words “1st day of November, 2007” shall be substituted;
- (b) for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

“TABLE

Place (1)	Rate (2)
Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs. 550 per month
Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2½% of pay subject to a maximum of Rs. 680 per month
Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs. 1570 per month”;

8. In regulation 24 of the said regulations, in sub-regulation (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) Medical Expenses.- On and from the 1st day of November 2007, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer’s own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior Management and Middle Management Grade	Rs. 5100 or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs. 6320 or the amount incurred whichever is less

Note.- (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above or;

- (ii) for the year 2007, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November 2007 and December, 2007.

Explanation. - for the purposes of this regulation,-

- (i) hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100 per cent in the case of an officer and 75 per cent, in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization or;
- (ii) on and from the 1st day of May, 2010, reimbursement of hospitalisation expenses under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme as laid down under the Bipartite Settlement dated the 27th day of April, 2010 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:-

TABLE

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	<p>(i) Bed Charges Self – Rs. 700 per day Family – Rs. 525 per day</p> <p>(ii) Other charges At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.</p>
--	---

(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII.	(i) Bed Charges Self – Rs. 900 per day Family – Rs. 675 per day (ii) Other charges At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.”;
--	---

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2007, a sum equal to 1.20 per cent, of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.25 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

10. In regulation 36 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely :-

“(3) With effect from the 1st day of May 2010, within the overall period of 12 months, leave may also be granted in case of hysterectomy upto a maximum of 45 days.”.

11. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(a) Halting Allowance – On and from the 1st day of May, 2010, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the Table below shall be entitled to ‘per diem’ Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:-

TABLE

Grades/Scales of officers	Major ‘A’ Class cities	Area I	Other Places
(1)	(2)		
	Rs.	Rs.	Rs.
Officers in Scale IV and above	1000	800	700
Officers in Scale I/II/III	800	700	600

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, Halting Allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz., Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs. 1200 and for officers in Scale I or II or III, the per diem Halting Allowance shall be Rs. 1000:

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.- For the purpose of computing Halting allowance “per diem” shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, “per diem” shall mean a period of not less than eight hours Rs. ’.

12. In regulation 42 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(4) On and from the first day of May 2010, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:-

“TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs. 12,000
Middle Management and Junior Management	Rs. 9,000”.

13. In regulation 44 of the said regulations, in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that with effect from the 1st May 2010, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC First Class fare by train for the distance travelled, whichever is less and the same rules shall apply to an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 kms.”.

14. In regulation 45 of the said regulations, -

- (i) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that there shall be no Provident Fund to Officers joining the services of the Banks on or after the 1st day of April, 2010.”;

- (ii) in sub-regulation (3), after clause (b) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(c) Officers who are covered under the Contributory Provident Fund Scheme who do not opt for Pension Scheme shall continue under the Contributory Provident Fund Scheme.”;

- (iii) after sub-regulation(3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(4) The officers joining the services of the Bank on or after the 1st day of April 2010 shall be covered by a Defined Contributory Pension Scheme, where the officer shall contribute ten per cent, of pay plus Dearness Allowance and the Bank shall make the similar amount of contribution in accordance with the provisions of the Contributory Pension Scheme in accordance with New Pension Scheme notified by the Central Government vide notification of the Government of India, F.No.5/7/2003-ECB & PR dated the 22nd December, 2003, as amended from time to time.”

15. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“Schedule to United Bank of India (Officers’) Service Regulations, 1979

(See sub-regulation (2) of regulation 23)

With effect from the 1st day of November, 2007, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs. 14,700/-	Pay above Rs. 14,700/-
1	2	3	4
1.	Mizoram		
	(a) Chhimtuipui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram.	2000	2600
	(b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram.	1600	2100
	(c) Throughout Aizawl District of Mizoram	1200	1500
2.	Nagaland	1600	2100
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	2000	2600
	(b) South Andaman (including Port Blair)	1600	2100
4.	Sikkim	2000	2600
5.	Lakshadweep Islands	2000	2600
6.	Assam	320	400
7.	Meghalaya	320	400
8.	Tripura		

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs. 14,700/-	Pay above Rs. 14,700/-
1	2	3	4
	(a) Difficult areas of Tripura	1600	2100
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	1200	1500
9.	Manipur	1200	1500
10.	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	2000	2600
	(b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	1600	2100
11.	Jammu and Kashmir		
	(a) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	2000	2600
	(b) Udhampur District:		
	(i) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, other than those included in Part 2(b).	2000	2600
	(ii) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	1600	2100
	(c) Doda District: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	2000	2600
	(d) Leh District : All places in the District	2000	2600
	(e) Barmulla District: Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqua	2000	2600
	(i) Matchill	1600	2100
	(f) Poonch and Rajouri District : Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	1200	1500
	(g) Areas not included in items (a) to (f) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	1200	1500
12.	Himachal Pradesh		
	(a) Chamba District		
	(i) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	2000	2600
	(ii) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in item (i) above.	1600	2100
	(iii) Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	1200	1500
	(b) Kinnaur District:		
	(i) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/ Charang Panchayats, 15/ 20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.	2000	2600
	(ii) Entire District other than Areas included in (a) above.	1600	2100
	(c) Ku2llu District:		
	(i) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	2000	2600
	(ii) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	1200	1500
	(d) Lahaul and Spiti District : Entire area of Lahaul and Spiti	2000	2600
	(e) Shimla District : (i) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	2000	2600

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs. 14,700/-	Pay above Rs. 14,700/-
1	2	3	4
	(ii) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghor Chaibis of Pargana Sarahan.	1600	2100
	(iii) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghor Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	1200	1500
	(f) Kangra District:		
	(i) Areas of Bara Bhawal and Chhota Bhawal	1600	2100
	(ii) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town-Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar. Palampur Town of Kangra District including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. Krishi Vishwavidyalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.	1200	1500
	(g) Mandi District:		
	Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gattoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.	1200	1500
	(h) Sirmaur District:		
	Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), BharogBheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract	1200	1500
	(i) Solan District :		
	Mangal Panchayat.	1200	1500
	(j) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in items (a) to (i) above.	320	400
13.	Uttarakhand		
	Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts.	2000	2600"

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

Sd/- ILLEGIBLE
General Manager(HR)

For & on behalf of United Bank of India H.O.

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India on.....and subsequently amended vide following notifications, namely:—

1. No. 01/2018, dated the 8th, day of January 2018
- 2.